P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आतंकवाद से प्रभावित होते भारत–पाकिस्तान संबंध

कमलेश चन्द्र पाण्डेय
अतिथि शिक्षक,
रक्षा एवं स्त्रॉतेजिक अध्ययन विभाग, बिड़ला परिसर,
हे0नं0ब0ग0केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड, भारत

राकेश चन्द्र सिंह कुँवर
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
रक्षा एवं स्त्रॉतेजिक अध्ययन विभाग, बिड़ला परिसर,
हे0नं0ब0ग0केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड भारत

सारांश

भारत व पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो ऐसे देश हैं, जिनके सम्बन्ध उनके जन्म से ही तनावपूर्ण रहे हैं। तनाव के बीच वार्ताओं का सिलसिला अधिक समय तक नहीं चल पाया।कश्मीर समस्या तथा अन्य मुद्दों को लेकर दोनों के मध्य 1947, 1965, 1971 तथा 1999 में चार बार बड़े सैनिक संघर्ष भी हो चुके हैं। इन सैनिक संघर्षों का परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन इनका संदेश यह अवश्य रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ सीधे सैनिक संघर्ष में विजय हासिल नहीं कर सकता है। अतः पाकिस्तान ने भारत के साथ सैनिक समानता हासिल करने के लिए भारत विरोधी देशों के साथ सैनिक गठजोड़ के साथ–साथ आण्विक शस्त्रों के विकास तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे अन्य साधन भी अपनाता रहा है। भारत पाक संबंधों में बढ़ते तनाव के लिए निश्चय ही पाकिस्तान के आंतरिक हालात उत्तरदायी रहे हैं। पाकिस्तान में फौज और नागरिक सरकार के बीच संबंध इसका सिर्फ एक पहलू है। पाकिस्तान पर चाहे सैनिक तानाशाह का शासन रहा हो या लोकतांत्रिक सरकार का शासन उनका व्यवहार नही बदलेगा। भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य वैश्विक मंचों पर भी उठाया है। इस मुद्दे पर भारत को काफी सफलता मिली है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के कारण वैश्विक पटल पर अलग–थलग होता जा रहा है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ आपसी समझ, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के दृष्टि से सक्रिय और सहयोगी संबंधों पर जोर देता रहा है। सिर्फ भारत विरोधी दृष्टिकोण ही पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता और समर्थन का आधार है, जबकि एक लोकतांत्रिक एवं समृद्धशाली पाकिस्तान ही भारत के हित में है। भारत इस नीति का सदैव समर्थक रहा है कि पाकिस्तान में स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली एवं राजनीतिक स्थिरता की स्थापना बनी रहे। और यदि पाकिस्तान की सरकार चाहे तो यह लोकतांत्रिक हित में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर कोई ठोस कदम उठाए।

मुख्य शब्द : संबंध, संघर्ष, आतंकवाद, लोकतंत्र।

प्रस्तावना

ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के पश्चात् एशिया महाद्वीप में एक नए संघर्ष की शुरूआत हुई जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से शान्ति शब्द का लोप ही हो गया। यह संघर्ष था दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देशों का संघर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत विभाजन के बाद से ही विभाजन के समय की घृणा और अविश्वास ने दोनों देशों को आज तक युद्ध की तैयारी में लगाए रखा है।[1] अगस्त 1947 में दो टुकड़ों में भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के राज्यों का निर्माण किया गया। जिसमें पाकिस्तान का जन्म साम्प्रदायिक आधार पर हुआ था। भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा दो राष्ट्रों के सिद्वांत का प्रतिपादन करते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की मांग रखी गई।[2] भारत व पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो ऐसे देश हैं, जिनके सम्बन्ध उनके जन्म से ही तनावपूर्ण रहे हैं। तनाव के बीच वार्ताओं का सिलसिला अधिक समय तक नहीं चल पाया। कश्मीर समस्या तथा अन्य मुद्दों को लेकर दोनों के मध्य 1947, 1965, 1971 तथा 1999 में चार बार बड़े सैनिक संघर्ष भी हो चुके हैं। इन सैनिक संघर्षों का परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन इनका संदेश यह अवश्य रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ सीधे सैनिक संघर्ष में विजय हासिल नहीं कर सकता है। अतः पाकिस्तान ने भारत के साथ सैनिक समानता हासिल करने के लिए भारत विरोधी देशों के साथ सैनिक गठजोड़ के साथ–साथ आण्विक शस्त्रों के विकास तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे अन्य साधन भी अपनाता रहा है। 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच 1972 में ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देश अपने विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के

आधार पर सुलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इसका पालन नहीं किया तथा वह निरंतर कश्मीर मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है।[3] औपनिवेशिक दौर की समाप्ति के बाद पहले इस्लामिक देश के रूप में स्थापित हुए पाकिस्तान का अतीत सत्तर वर्षों में खतरनाक ही रहा है। आगे भी उसका भविष्य अनिश्चित ही दिखता है। वहां कायम जिहादी संस्कृति ने अलगाववाद को बढ़ावा देने के साथ ही उसे गंभीर वित्तीय संकट में धकेल दिया है। इसके चलते पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब जैसे अपने रहनुमाओं का मोहताज बनकर रह गया है। सेना और आतंकी समूहों की लंबे समय से चली आ रही साठगांठ ने पाकिस्तान की समस्याओं को कई गुना बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित 22 आतंकी समूह सक्रिय हैं। पाक सेना उन्हें अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान धार्मिक कट्टरवाद और सीमा पर आतंकवाद संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय धारणाओं को स्वीकार करने से इनकार करता रहा है। वह विभिन्न प्रकार के आतंकवादी गुटों की गतिविधियों को जेहाद की संज्ञा देता है जो उनकी इस्लामी धर्मग्रंथों की व्याख्या के अनुसार आंतरिक व बाह्य रूप से धार्मिक आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष जारी रखना है। उनके अनुसार जेहाद एक आध्यात्मिक और धार्मिक विषय है और उसका उद्देश्य *उम्माह अर्थात् विश्व के मुसलमानों के खिलाफ किसी प्रकार के अत्याचार व अन्याय के विरूद्ध संघर्ष* है।[4] भारत पाक संबंधों में बढ़ते तनाव के लिए निश्चय ही पाकिस्तान के आंतरिक हालात उत्तरदायी रहे हैं। पाकिस्तान में फौज और नागरिक सरकार के बीच संबंध इसका सिर्फ एक पहलू है।[5] पाकिस्तान पर चाहे सैनिक तानाशाह का शासन रहा हो या लोकतांत्रिक सरकार का शासन उनका व्यवहार नही बदलेगा। सत्ता पर चाहे कोई भी हो लेकिन पर्दे के पीछे से शासन चलाने वाले वहां के मुल्ला और सैनिक अधिकारी ही होते हैं। हर पल वह भारत के सर्वनाश की इच्छा करते हैं। देश का मुस्लिम अगर सज्जन है और यदि भारत के साथ शांति और सद्भाव चाहने वाला है तो पर्दे के पीछे के लोग उसे एक कदम आगे बढ़ने नहीं देंगे।[6] पाकिस्तान के जेहादी समूह मुख्य रूप से दो सैन्य तानाशाहों जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन में पनपे। सैन्य असैन्य प्रतिष्ठान के असहज संबंध पाकिस्तान की नाकामी एक बड़ी वजह हैं। पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई इतनी ताकतवर है कि वे नागरिक सत्ता की निगरानी के दायरे में नहीं है। इससे वे मनमाने ढंग से दखल देती है। चुनी हुई सरकार होने के बावजूद निर्णायक शक्ति जनरल के पास है। इससे उन्हें आतंकी समूहों से रिश्ते कायम रखने का अधिकार मिल जाता है। 12 नवम्बर 1998 को भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद तथा मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में वार्ता की गई जिसमें भारत का नेतृत्व गृह सचिव वीपी सिंह तथा पाकिस्तान के नेतृत्व वाली गृह सचिव हफीजुल्ला इशाद ने किया। लेकिन उपरोक्त वार्ता पर भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। जिससे वार्ता असफल ही रही।[7] हालांकि भारत पाकिस्तान संबंधों के उतार–चढ़ाव के लंबे पथ में महत्वपूर्ण पड़ाव उस समय आया जब दोनों देशों द्वारा अक्टूबर 2002 के दूसरे पखवाड़े में सीमा पर तैनात अपनी–अपनी सेनाओं को हटाने का फैसला किया। इस संबंध में सबसे पहले पहल भारत द्वारा दिखाई गई। लेकिन जम्मू–कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनाती में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। भारत सरकार के प्रत्युत्तर में सकारात्मक जबाव देते हुए पाकिस्तान ने भी 17 अक्टूबर 2002 को भारत से सटी सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को बैरकों में वापस भेजने की घोषणा कर दी। फलतः दोनों देशों द्वारा उठाए गए इन कदमों से सीमा पर करीब 10 माह से जारी तनाव में काफी कमी आई।[8] अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के कईं देशों के प्रयासों से जुलाई 2010 में दोनों देशों के बीच पुनः वार्ता प्रक्रिया आरम्भ हुई। यद्यपि जुलाई 2010 में भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की, लेकिन सम्बन्धों को सुधारने में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। इसी बीच जुलाई 2011 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा व्यापार को आगे बढ़ाने तथा कतिपय सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की। वार्ताओं के इस नए क्रम में बातचीत में उन्हीं आठ मुद्दों को शामिल किया गया है, जो समग्र वार्ता में शामिल थे, लेकिन इन वार्ताओं का नाम बदलकर व्यापक वार्ता रखा गया है, लेकिन जब भी इन वार्ताओं का आयोजन किया जाता था तो पाकिस्तान के भारत स्थित राजदूत कश्मीर के अलगाववादी हुर्रियत नेताओं से वार्ताओं के पूर्व दिल्ली में अलग से विचार–विमर्श करने लगे। भारत ने इस बात का विरोध किया तथा वार्ताएं आगे नहीं बढ़ पाई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच अनौपचारिक बातचीत ने इन वार्ताओं को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसी क्रम में नवम्बर 2015 में जब भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यात्रा की तो इस बात पर औपचारिक सहमति बनी कि शीघ्र ही दोनों देश व्यापक वार्ताओं की शुरूआत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि ये वार्ताएं शुरू हो पातीं कि जनवरी 2016 से ही भारत पाकिस्तान के बीच आतंकवाद के मामले पर पुनः तनाव बढ़ गया है तथा ये वार्ताएं फिर से रूक गई हैं।[9]

अफगान संसद का उद्घाटन के बाद 25 दिसम्बर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच कर नवाज शरीफ की नातिन के निकाह में न केवल शामिल हुए बल्कि पिछले 10 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अचानक यात्रा करके यह साबित कर दिया कि भारत, पाकिस्तान से सभी मुद्दों पर समग्र बातचीत करने का इच्छुक है किन्तु पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को पोषित कर रहा है। पाकिस्तान सीमा पर हरकतें करता ही चला जा रहा है। भारतीय सैनिकों के सिर काटने से लेकर पूंछ क्षेत्र में पांच भारतीयों की हत्या, पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला, कश्मीर सहित सीमा पर आये दिन गोलाबारी हो रही है। अफगानिस्तान से नाटो सेना की वापसी के बाद जिहादी फैक्ट्री के पास काम का अभाव है, इसलिए पाकिस्तान इन जेहादियों को भारत की ओर मोड़ता जा रहा है। हालात

यह हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार भी अब एशिया में वर्चस्व के लिए एकजुटता की बात करने के बजाय कश्मीर की आजादी के लिए अंत तक लड़ने की बात कहने लगे हैं। इसके बावजूद भी मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान को साफ संकेत हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, किन्तु दोनों देशों के संबंध कभी सामान्य नही हो सकते हैं।[10] पाकिस्तान में आतंकवाद के कारण पिछले पांच वर्षों में 8,500 से अधिक असैनिक लोगों और सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हो गई। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान नेशनल असेंबली में यह आंकड़ा साझा किया। आंकड़ें के अनुसार इस अवधि के दौरान आतंकवाद के चलते कुल 5,532 असैनिक लोगों की जान गयी और 10,195 लोग घायल हुए। इसी अवधि में 3,157 सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हुई और 5,998 कर्मी घायल हुए।

फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया में सबसे अधिक 71,487 सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हुई और 2,224 कर्मी घायल हुए इसी अवधि में इस क्षेत्र में 1,470 असैनिक लोगों की मौत हुई और 2,761 लोगों को चोंटें आई। पिछले पांच वर्षों में कुल 3,759 आतंकी मारे गए। फाटा में 2,530, पंजाब में 90, सिंध में 342, खैबल पख्तूनख्वा में 351, बलूचिस्तान में 435, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र में सात, पाक अधिकृत कश्मीर में तीन ओर गिलगित बाल्टिस्तान में एक आंतकी मारे गए। इस दौरान कुल 173 आतंकियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान के अनुसार 9 सितम्बर 2001 की अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवाद को लेकर शुरू हुई लड़ाई में अब तक 55,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं इसके चलते देश की अर्थ व्यवस्था को 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।[11] वर्ष 2016 से लेकर 08 मई 2019 तक पाकिस्तान में व्याप्त आतंकवाद जनित हिंसा को निम्न सारणी द्वारा समझा जा सकता है–[12]

वर्ष	आत्मघाती हमले	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षाकर्मी	मारे गए आतंकी / उग्रवादी	मारे गए अज्ञात
2016	522	543	279	897	68
2017	295	440	215	533	81
2018	163	359	163	161	14
2019	51	73	54	29	0
कुल	**1031**	**1415**	**711**	**1620**	**163**

source: www.satp.org

भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य वैश्विक मंचों पर भी उठाया है। इस मुद्दे पर भारत को काफी सफलता मिली है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के कारण वैश्विक पटल पर अलग–थलग होता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान से संचालित आतंकवाद के ही कारण नवम्बर 2016 में इस्लामाबाद में सम्पन्न होने वाले सार्क के शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था। भारत के निर्णय का समर्थन करते हुए अफगानिस्तान, भूटान तथा बांग्लादेश ने भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था। परिणास्वरूप सार्क का यह शिखर सम्मेलन आज तक सम्पन्न नही हो सका। इन घटनाओं के ही कारण भारत व पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित व्यापक वार्ताओं पर भी विराम लग गया है इन वार्ताओं में दोनों देशों के द्वारा आपसी सहमति से आठ बिन्दुओं पर बातचीत की जानी थी। वर्ष 2015 में दोनों देशों द्वारा इन वार्ताओं को आरम्भ करने की सहमति बनी थी।[13]

जनवरी 2016 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारत के पठानकोट एयरबेस पर घातक हमला किया था, जिस पर भारत द्वारा गम्भीर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। इसके बाद जुलाई 2016 में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहदीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत हो गई। पाकिस्तान द्वारा बुरहान वानी को शहीद घोषित किया गया। इस घटना के बाद में जम्मू–कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई जिसे पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। उल्लेखनीय है कि हिजबुल मुजाहदीन कश्मीर घाटी में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है जिसके आतंकवादियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें हथियार व वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। पुनः सितम्बर 2016 में आतंकवादियों ने कश्मीर के उड़ी स्थित सैन्य शिविर पर हमला किया। भारत को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की यह सीधी चुनौती थी।[14] जैश–ए–मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना भारत की मजबूत रणनीति का हिस्सा है जिसने आतंकवाद जैसे गंभीर मसले पर सम्पूर्ण विश्व को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरे विश्व का ध्यान इस ओर ले जाने की आवश्यकता है कि आतंकवाद सिर्फ भारत–पाक का मुद्दा ना रहकर विश्व के लगभग हर भाग में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है।[15] उम्मीद है कि मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने की बात पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। अंततः उन सभी नान स्टेट एक्टर्स को समाप्त करना होगा, जो नफरत अलगाववाद और सांप्रदायिकता को हवा देते हैं। उनको मिल रही धनराशि को रोकना होगा साथ ही आतंकवादियों के संगठित क्षमताओं को खत्म करना होगा। इन सब तथ्यों को राष्ट्रीय कार्ययोजना में शामिल कर क्रियान्वयन हेतु इच्छाशक्ति को मजबूत करना होगा। यदि ऐसा हो पाता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में शांति स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। भारत अपने पड़ोसियों के साथ आपसी समझ, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के दृष्टि से सक्रिय और सहयोगी संबंधों पर जोर देता रहा है। अमेरिकन सी0आई0ए0 के पूर्व

निदेशक रहे माइकल मोरेल ने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के खिलाफ आतंवाद का प्रयोग हथियार के तौर पर करते हैं। साथ ही इस प्रकार की नीति को अफगानिस्तान में भी दोहराया जाता है क्योंकि पाकिस्तान को आफगानिस्तान में भारत के बढ़ते प्रभाव का भय है। इसी लिए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए आंतकी संगठनों को खड़ा किया है। मोरेल का मानना है कि सामाजिक दृष्टिकोण से आतंकवाद बढ़ रहा है और यदि पाकिस्तान के हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में पाकिस्तान में अरब जैसी क्रांति देखने को मिल सकती है। जिसने कहीं न कहीं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित होगी। जेहादी आतंकवाद का बहावी विचारधारा से गहरा जुड़ाव है। इस हिंसक एवं असहिष्णु धारा को सऊदी अरब सहित कई देश वित्त पोषित कर रहे हैं। बहाबी कट्टरता जहां आतंकवाद की वैचारिक धुरी है वहीं आई.एस., अलकायदा, तालिबान, लश्कर–ए–तैयबा और बोको हराम आतंक को अमली जामा पहनाने वाली कड़ियां।[16]

अध्ययन का उद्देश्य

भारत व पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के दो ऐसे देश हैं, जिनके सम्बन्ध वर्ष 1947 से ही तनावपूर्ण रहे हैं। इन दोनों ही देशों में तनाव के बीच सफल वार्ताओं का सिलसिला अधिक समय तक नहीं चल पाया। जिसका एक कारण आतंकवाद भी है। आतंकवाद से पाकिस्तान को भी काफी क्षति यथा सामाजिक एवं आर्थिक हो रही है। वहीं भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में आतंकवाद के कारण मधुरता नहीं आ पा रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में आतंकवाद के कारण दोनों देशों के आपसी संबंधों में हो रहे परिवर्तन को समझाते हुए वर्तमान संबंधों की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। साथ ही शोध पत्र का उद्देश्य एवं सुझाव यह भी है कि पाकिस्तान यदि आतंकवाद एवं आतंकवादियों को अपना सहयोग/समर्थन नहीं देता है तो यह कदम दोनों ओर की जनता के लिए काफी कल्याणकारी और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण दो पड़ोसी देशों के सम्बन्ध आज भी मधुर नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में विकास एवं सुदृढ़ लोकतंत्र होने का अभाव प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली से अछूता रह गया है। फलतः राजनीतिक स्थिरता एवं प्रबल लोकतांत्रिक जनमत के अभाव में सैनिक शासकों एवं महामुल्लावादी तत्वों के पाकिस्तान की राजनीतिक प्रक्रिया में प्रभावशाली भूमिका प्राप्त की है। पाकिस्तान का मकसद आतंकियों को प्रशिक्षण देकर भारत भेजना रहा है। आजादी के पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में विकास की गति बहुत धीमी रह गई है। सिर्फ भारत विरोधी दृष्टिकोण ही पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता और समर्थन का आधार है, जबकि एक लोकतांत्रिक एवं समृद्धशाली पाकिस्तान ही भारत के हित में है। भारत इस नीति का सदैव समर्थक रहा है कि पाकिस्तान में स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली एवं राजनीतिक स्थिरता की स्थापना बनी रहे। और यदि पाकिस्तान की सरकार चाहे तो यह लोकतांत्रिक हित में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर कोई ठोस कदम उठाए। जिससे कि वह अपने देश के नागरिकों को एक बेहतर भविष्य उपलब्ध करा पाए। साथ ही भारत से मधुर सम्बन्धों को बढ़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की विकास प्रक्रिया में अहम् भूमिका अदा करे। लेकिन जब तक पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का प्रयोग हथियार के तौर पर होता रहेगा तब तक भारत पाकिस्तान के मध्य शान्ति स्थापना एक कल्पना मात्र है।

अंत टिप्पणी

1. *फड़िया, डॉ0 बी0एल0, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, (1997) पृ0सं0–380*
2. *वर्मा, डॉ0 दीनानाथ, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, (2006) पृ0सं0–344*
3. *प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर 2018, पृ0सं0–76*
4. *दीक्षित, जे0एन0, भारत पाक संबंध (युद्ध एवं शांति में), (2004) पृ0सं0–445*
5. *पंत, डॉ0 पुष्पेश जैन, श्री पाल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, सिद्धांत एवं व्यवहार, (2013) पृ0सं0–461*
6. *शास्त्री,एम0वी0आर0, कश्मीर गाथा, (2004) पृ0सं0–131*
7. *प्रसाद, मुद्रिका, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, (2011) पृ0सं0–205*
8. *शर्मा, डॉ0 मथुरालाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, (2013) पृ0सं0–182*
9. *प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर 2018, पृ0सं0–76*
10. *सिंह, डॉ0 लल्लन जी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षाएं (2017) पृ0सं0–514*
11. *राष्ट्रीय सहारा, देहरादून संस्करण, 29 नवम्बर, 2015*
12. *https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan*
13. *प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर 2018, पृ0सं0–75*
14. *प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर 2018, पृ0सं0–74*
15. *पूर्वांचल प्रहरी, भारत की बड़ी जीत, 04 मई 2019*
16. *दैनिक जागरण, देहरादून संस्करण, 04 मई 2019*